**उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजना**

2062. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि मंजूर की थी, और

(ख) इस वर्ष के दौरान एवं वर्ष 1993-94 तक इन योजनाओं के तहत कितने गांव शामिल किये गये अथवा उन्हें शामिल किये जाने का विचार है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) केन्द्र सरकार ने 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को पेयजल सप्लाई तथा अन्य प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात (1) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (3) जवाहर रोजगार योजना के लिए स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :–

| कार्यक्रम | रिलीज की गई राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|
| 1. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 5505.00* |
| 2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 6843.74 |
| 3. जवाहर रोजगार योजना | 47110.02 |

*(1) समस्याग्रस्त गांवों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है।

(2) केन्द्र द्वारा योजना/परियोजनावार निधियां रिलीज नहीं की जाती है लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

(ख) 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 2487 गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है।

**No-Source Category Villages in the Country**

2063. SHRI MURIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of no-source category villages, State-Wise ;

(b) the targets set for providing drinking water in No-source cotegory villages during the last three years ;

(c) what has been the performance against the targets ; and

(d) the steps taken by Government to accelerate the pace of providing safe drinking water in all villages ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) The Statewise number of no-source problem villages as on 31-10-93 is as under :

| | |
|---|---|
| Assam | 9 |
| Gujarat | 9 |
| Jammu & Kashmir | 207 |
| Maharashtra | 22 |
| Meghalaya | 252 |
| Orissa | 16 |
| Rajasthan | 47 |
| Tripura | 3 |
| Uttar Pradesh | 92 |
| TOTAL | 657 |

(b) and (c) The targets set for providing drinking water in No-Sources problem villages an performance against the targets during the last three years is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXIX, Annexure no 50]

(d) The Central Government had allocated special allocation of Rs. 190 crores in 1991-92 and 1992-93 to the concerned States to accelerate the pace of provision of safe drinking water facilities in the remaining No-Source problem villages. The progress of coverage in Non-Source villages is being monitored closerly and rtveiewed from time to time with the various States,

the last review was held on 14th October, and 15th October 1993, Most of the remaining No-Source villages are targetted to be covered with safe drinking water facilities by 31-3-94.

**Funds Released under the Scheme for Assured Employment**

2064. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have released Rs. 87.6 crores to the States under the Scheme for Assured Employment to the Rural Poor in the revamped Public Distribution Blocks ;

(b) if so, what is the total amount so far released for all the 1752 blocks under the revamped PDS System ;

(c) if so, whether the main objective of the Scheme is to provide wage employment to agricultural labour and other workers who are in need of employment especially during the lean agricultural season;

(d) what is the total amount provided to Gujarat so far ;

(e) whether Government have sent detailed guidelines to the States for making the Scheme a success ; and

(f) whether Government have received the report from State Governments ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Including the State's matching share, the total amount so far released for all the 1752 blocks under the revamped PDS is Rs. 109.3875 crores.

(c) Yes, Sir.

(d) Including the State's matching share, Rs. 606.25 lakhs have been provided for implementation of EAS in Gujarat.

(e) and (f) Yes, Sir.

**बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायत भवनों का निर्माण**

2065. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार प्रदेश के दरभंगा जिला स्थित विकास खण्ड के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के अधीन वर्ष 1992-93 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ;

(ख) यह राशि किन-किन कार्यों के लिए निर्धारित की गयी थी तथा क्या-क्या कार्य किए गए हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए एक भवन निर्मित किया गया है ;

(घ) क्या ग्राम-ब्रिसुहानी में भी एक पंचायत भवन का निर्माण विचाराधीन है, यदि हां, तो वहां कब तक भवन निर्मित हो जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उपरोक्त गांव को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राशि के उपयोग में कोई घोटाला हुआ है ; और

(च) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां जवाहर रोजगार योजना के मैनुअल में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर केवल जिलों और ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाती हैं और न कि जिले के विकास खण्डों को। इसलिए 1992-93 के दौरान दरभंगा जिले के विकास खंडों को निधियां आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।